महत्वपूर्ण एवं खास

दो बाइक की भिड़ंत में एक युवक की हुई मौत

कांकेर (आरएनएस)। जिले के पखांजूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ताज मज्जित चौक के पास बीती देर शाम करीब 06 बजे तेज रफ्तार दो बाइक की आमने-सामने हुई भिड़त में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीवी -55 निवासी सपन दास ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका भतीजा सुभाष दास उम्र 40 वर्ष पिता निखिल अपने घर पीवी 46 से मोटर सायकल क्रमाक सीजी 19 बीसी 2809 से पखांजूर बाजार की तरफ जा रहा था। शाम करीब 06 बजे वह ताज मज्जित चौक में एमआरएफ शोरूम के सामने पहुंचा ही था कि सामने से आ रही बाइक क्रमांक सीजी-19 बीसी 3240 के चालक द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए उसकी बाइक को सामने से टक्कर मार दिया। दुर्घटना में सुभाष के सिर में गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

नक्सलियों द्वारा लगाए गए दो पाईप बम बरामद

सुकमा (आरएनएस)। जिले चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर थाना फुलबगड़ी से डीआरजी व छसबल की संयुक्त टीम ग्राम बंडेमपारा, सिंगनपानरा, ईत्तापारा की ओर रवाना हुए थे। अभियान के दौरान ग्राम बंडेमपारा ईत्तापारा के मध्य नक्सलियों द्वारा सुरक्षाबलों को क्षति पहुंचाने की नीयत से लगाए गए 02 पाईप बम बरामद किया गया। सुरक्षा बल के जवानों के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, उक्त बरामद पाईप बम को बीडीएस टीम के द्वारा सुरक्षित तरीके से निष्क्रीय कर दिया गया।

सेमरहा पहुंचा हाथियों का दल

कोरबा (आरएनएस)। वनमंडल कटघोरा के पसान रेंज के बनिया जंगल में विचरण कर रहे 20 हाथियों का दल बीती रात आगे बढक़र सेमरहा परिसर पहुंच गया। हाथियों के इस दल को आज सुबह यहां विचरण करते हुए देखा गया और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। जिस पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर हाथियों की निगरानी में जुट गया है। पसान रेंज में धर्मेन्द्र चौहान ने बताया कि वन विभाग द्वारा आसपास के गांवों में मुनादी करा दी गई है। हाथियों ने फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है लेकिन हाथियें के उत्पात की संभावना को देखते हुए वन अमला सतर्क हो गया है।

ग्रामीणों की हत्या में शामिल एक नक्सली जन मिलिशिया सदस्य ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान लोन वर्राटु अभियान के तहत तीन ग्रामीणों की हत्या में शामिल नक्सली जन मिलिशिया सदस्य मंगलू पोडियम ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सली मंगलू पोडियम इंद्रावती एरिया कमेटी के अंतर्गत पितांपर पंचायत में जन मिलिशिया सदस्य के रूप में काम करता था। ग्रामीणों को बहला-फुसलाकर नक्सली संगठनों में जोडऩे का काम करता था, कई ग्रामीणों की हत्याओं में भी मंगलू शामिल था। लगातार नक्सली लोन वर्राटू के तहत आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अब तक 516 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 127 इनामी नक्सली शामिल हैं।

दिशा समिति की आज होने वाली बैठक स्थगित

रायपुर (आरएनएस)। जिला समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) के अध्यक्ष रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी की अध्यक्षता में 15 फरवरी को होने वाली समीक्षा बैठक आरिहार्य कारणों से आगामी तिथि तक स्थगित की गई है। आगामी बैठक की सूचना पृथक से दी जाएगी।

छपरटोला फीडर जलाशय के काम को तेजी से शुरू कराने जल संसाधन मंत्री चौबे ने दिए निर्देश

❒ सीआईडीसी बोर्ड बैठक में तीन सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर हुई चर्चा

रायपुर (आरएनएस)। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में सीआईडीसी बोर्ड बैठक हुई। बैठक में अहिरन-खारंग लिंक परियोजना तथा छपराटोला फीडर जलाशय के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति सहित रेहर अटेम लिंक परियोजना के सर्वेक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री रविन्द्र चौबे ने सीआईडीसी के प्रबंध संचालक को छपराटोला फीडर जलाशय के काम को तेजी से शुरू कराए जाने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति सहित अन्य प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव जल संसाधन अन्बलगन पी., राजस्व सचिव एन.एन एक्का, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर वितरण कंपनी के चेयरमेन अंकित आनंद, मुख्य अभियंता जल संसाधन आई.के. उइके, सीआईडीसी के प्रबंध संचालक अनिल राय, उप प्रबंध संचालक जयंत पवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि उक्त तीनों सिंचाई परियोजनाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को छपराटोला फीडर जलाशय के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर काम शुरू कराए जाने से निर्देश दिए। मंत्री चौबे ने कहा कि अहिरन-खारंग लिंक परियोजना से खारंग जलाशय में जलापूर्ति और वहां से बिलासपुर शहर एवं रतनपुर कस्बे को पेयजल की आपूर्ति किया जाना है। इसको ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन के तहत जल के परिवहन, ट्रीटमेंट तथा वितरण हेतु आवश्यक अधोसंरचना एवं ओव्हर हेड टैंक का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल की आपूर्ति के लिए अरिहन-खारंग लिंक परियोजना के काम को कराए जाने की जरूरत है।

मंत्री चौबे ने रेहर अटेम लिंक परियोजना के सर्वेक्षण कार्य के बारे में भी सीआईडीसी और जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि रेहर अटेम परियोजना के सर्वेक्षण का कार्य अंतिम चरण में है। तीन माह के भीतर सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य की उक्त तीनों महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य सीआईडीसी के माध्यम से कराया जाना है। बैठक में जानकारी दी गई कि छपराटोला फीडर जलाशय का निर्माण अरपा नदी पर कोटा तहसील के ग्राम छपरापारा के पास प्रस्तावित है। इसकी लागत लगभग 968 करोड़ रूपए है। छपराटोला फीडर जलाशय का निर्माण का उद्देश्य अरपा नदी का संरक्षण कर ग्रामीणों की आजीविका के साधन बढ़ाने, 22 गांवों में भू-जल संवर्धन तथा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है।

इसी तरह अहिरन खारंग लिंक परियोजना, पेयजल आधारित परियोजना है, जिसकी लागत 720.52 करोड़ रूपए है। इस परियोजना के अंतर्गत कोरबा जिले के कटघोरा विकासखण्ड के ग्राम पोड़ी गोसाई के समीप अहिरन नदी पर बांध निर्माण कर वहां संग्रहित जल को पाईप लाईन के जरिए खारंग जलाशय में लाया जाएगा। खारंग जलाशय से नगर पालिक निगम बिलासपुर को 31 मिलियन घन मीटर तथा रतनपुर शहर को 1.11 घन मीटर जल की आपूर्ति पेयजल के लिए की जाएगी। रेहर-अटेम लिंक परियोजना के माध्यम से सरगुजा जिले की रेहर नदी को हसदेव नदी से जोड़ा जाना है। सूरजपुर जिले के डेडरी ग्राम के समीप रेहर बैराज निर्माणाधीन है। जहां से पानी चैनल के माध्यम से ग्राम परसापाली के समीप बिछली नाला में छोडक़र झिंक नदी से जोडऩा प्रस्तावित है।

एसईसीएल में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण 31 मार्च तक

कोरबा(आरएनएस)। एसईसीएल अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण आगामी 31 मार्च कर लिया जाएगा। वहीं भू.विस्थापितों के लंबित मामलों का भी जल्द निपटारा किया जाने का आश्वासन निदेशक कार्मिकए तकनीकी एमके प्रसाद ने संचालन समिति की बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि अल्टरनेट जाब के लिए शीघ्र बोर्ड का गठन किया जाएगा।

साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड एसईसीएल की संचालन समिति की बैठक गेवरा स्थित सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में पांचो श्रमिक संघ एचएमएस से नाथूलाल पांडेय, एटक से हरिद्वार सिंह, एसईकेएमसी इंटक से गोपाल नारायण सिंह, सीटू से वीएम मनोहर व बीएमएस से मजरूल हक शामिल हुए। बैठक में श्रमिक संघ प्रतिनिधियों ने कई प्रस्ताव रखा। इसमें सबसे अहम प्रस्ताव अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित रहा। बताया जा रहा है कि लगभग 200 प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति के लंबित हैं। इसके साथ ही भू-विस्थापित व कोरोना से दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को नौकरी देने के मामले का भी निराकरण किया जाना है। एचएमएस अध्यक्ष नाथूलाल पांडेय ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण गंभीरता से निराकरण किए जाने चाहिए, ताकि दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को समय पर नौकरी मिल सके और उनका परिवार बेहतर ढंग से जीवन यापन कर सके। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर इन प्रकरणों का निराकरण होना चाहिए। क्षेत्रीय कार्यालय से 10 दिन के भीतर फाइल तैयार कर मुख्यालय भेजा जाए और मुख्यालय में पांच दिन के भीतर इन प्रकरणों का निराकृत कर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना चाहिए। इस पर निदेशक तकनीक मनोज कुमार ने आश्वस्त किया कि रोजाना दो घंटे अनुकंपा नियुक्ति के मामले निपटाने के लिए निर्धारित किया गया है और कोशिश है कि आगामी 31 मार्च तक सभी प्रकरण का निराकरण कर लिया जाए। इस मौके पर एसईकेएमसी के केंद्रीय अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने भी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे प्रबंधन के समक्ष प्रमुखता से रखते हुए निराकरण करने कहा। इस पर प्रबंधन ने कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। इस मौके पर प्रबंधन की ओर महाप्रबंधक कार्मिक, महाप्रबंधक मेडिकल व महाप्रबंधक सिविल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

लापता युवक का शव रेत में दबा मिला, जांच में जुटी पुलिस

रायपुर (आरएनएस)। बलौदाबाजार से लापता युवक का शव सोमवार को महासमुंद में मिला है। शव को रेत में दफन किया गया था। ग्रामीणों ने देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद युवक की शिनाख्त हो सकी। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर भिजवा दिया है। मामला साकरा थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, साकरा के ग्राम चारभाटा और डुमर पाली के बीच कंतरा नाला है। ग्रामीण सोमवार को काम करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें नाले में रेत के नीचे कुछ दबा हुआ दिखाई दिया। इस पर ग्रामीणों ने

रेत हटाई तो देखा कि एक युवक का शव था। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आसपास के थानों और जिलों में तस्वीर भेजी तो युवक की शिनाख्त बलौदाबाजार में राजा देवरी क्षेत्र के डुमर पाली गांव निासी बीसी केशन (35) के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि युवक 26 जनवरी से लापता था। वह घर से निकला, इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इस पर परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

विद्युत उपकेंद्र छिरहा, सिलघट एवं पिरदा में पॉवर ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई

❒ दर्जन भर से अधिक गांवों के उपभोक्ताओं को मिलेगी निर्बाध बिजली

दुर्ग (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दुर्ग क्षेत्र, उपभोक्ताओं एवं किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर तेजी से कार्य कर रही है। इसी तारतम्य में दुर्ग क्षेत्र के विभागीय संभाग बेमेतरा एवं साजा के अंतर्गत 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्रों छिरहा, सिलघट एवं पिरदा में पॉवर ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाकर उन्हें क्रियाषील कर दिया गया है। तीनों उपकेंद्रों में पूर्व से स्थापित 1-1 नग पॉवर ट्रांसफरों की क्षमता 3.15 एम.व्ही.ए. से बढ़ाकर 05 एम.व्ही.ए. किया गया। विद्युत उपकेंद्रों में पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत लगभग 87 लाख रुपए की लागत से संपन्न किया गया। परियोजना संभाग के कार्यपालन अभियंता पी.के. षर्मा ने बताया कि तीनों उपकेंद्रों के पॉवर ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने से विद्युत उपकेंद्र छिरहा के अंर्तगत ग्राम छिरहा सहित झांकी, नवांगांव, बिरसिंधी आदि, उपकेंद्र सिलघट के अंतर्गत ग्राम सिलघट सहित कुसमी, बेरला, तारालिम आदि एवं उपकेंद्र पिरदा के अंतर्गत ग्राम बारगांव, बलौदी, जमघट एवं चेटवा आदि ग्रामों के किसाानों एवं उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज एवं ओवर लोडिंग की समस्या से राहत मिलेगी एवं सभी घरों और पंपों तक उच्च गुणवत्ता की बिजली पहुंचेगी।

कुटुम्ब न्यायालय में रिक्त पद में भर्ती के लिए आवेदन 14 मार्च तक आमंत्रित

कोरबा(आरएनएस)। कुटुम्ब न्यायालय कोरबा में रिक्त आदेशिका वाहक (चतुर्थ श्रेणी) अन्य पिछड़ा वर्ग के एक पद की भर्ती के लिए आवेदन 14 मार्च 2022 तक आमंत्रित किया गया हैं। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन 14 मार्च संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कोरबा के नाम से भेजना होगा।

आवेदकों को बंद लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद आदेशिका वाहक लिखना होगा। आवेदित पद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी पात्र होंगे। पद के लिए 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला कक्षा 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

अध्यक्ष भर्ती समिति कुटुम्ब न्यायालय कोरबा ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, जाति, स्थायी निवास, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन एवं आयु में छूट संबंधी दस्तावेज इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ स्व-प्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा होना चाहिए। आवेदकों को पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, पेनकार्ड आदि की भी स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। ई-मेल, फैक्स, कोरियर के द्वारा प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। विज्ञापन का विस्तृत विवरण तथा आवेदन का प्रारूप कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आवेदन का प्रारूप अवलोकन कर डाउनलोड किया जा सकता हैं।

बेशकीमती सागौन पेड़ों की अवैध कटाई पसरखेत में जारी

कोरबा (आरएनएस)। वनमंडल कोरबा में पसरखेत वन परीक्षेत्र कार्यालय से महज तीन किलोमीटर दूर माझीडेरा में हरे भरे बेशकीमती सागौन और खम्हार के पेड़ की अंधाधुंध कटाई जारी है। इसकी गवाही ताजे ठूंठ की यह तस्वीरें खुद ही बयां कर रहीं हैं। ऐसी स्थिति में वनरक्षकों पर सवाल खड़े होते हैं कि जब कार्यालय से लगे जंगलो की सुरक्षा नहीं हो रही तो पूरे वन परिक्षेत्र का क्या हाल होगा। इसकी महज कल्पना ही कि जा सकती है। वन विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं।

हरे-भरे सागौन और खम्हार दिनों वन माफिया के खास निशाने पर है। यहां आसानी से पेड़ों की कटाई कर सुगमता के वन माफिया ले जा रहे है

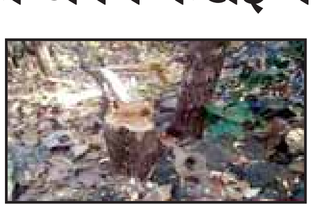

पहुंचा रहे हैं। हरे भरे सागौन के पेड़ इमारती लकड़ी की जमकर कटाई की जाती है। इसे देख कर यह प्रतीत हो रहा है कि जब जंगलों के यह हाल है तो आस पास के ग्रामीण अंचलों में वन परिक्षेत्र के आने वाले जंगलो जंगल के क्या हाल होंगे। जिस गति से वन माफिया बेखौफ होकर दिन दहाड़े इन जंगलों में पेड़ों की कटाई कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उन्हें पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं है और वन विभाग को भी इसकी कोई खबर नहीं हो रही है। पेड़ों की बाकायदा कटाई के लिए वन माफिया कटर मशीन का उपयोग कर रहे है। वनविभाग की नाक के सामने से बड़ी मात्रा में सागौन के बेशकीमती इमारती लकड़ी चुराकर ले जा रहे हैं इससे कहीं न कही विभागीय लापरवाही उजागर होती हैं। वन प्रबंधन समिति मदनपुर के अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह राठिया का कहना है कि वन प्रबंधन समिति का कोई महत्व नहीं है कभी बैठक नही होता है वन रक्षको की मनमानी है। जंगल में पेड़ कट रहे हैं। वहीं वन प्रबंधन समिति पसरखेत के अध्यक्ष धनसिंह राठिया ने कहा कि हमारा कोई महत्व नहीं है केवल नाम का अध्यक्ष हूँ जंगल में पेड़ कट रहा है,रेजर बात नहीं करता। उप वनमंडलाधिकारी कोरबा आशीष खेलवार का इस संबंध में कहना है कि पसरखेत रेंज में पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायत मिली है। मामले की जांच करवाई जा रही है। जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

सोनहत के ग्राम पोड़ी में बसे 22 वनवासियों के चेहरों पर मुस्कान लिखेगी नई कहानी

❒ 30 एकड़ में किसानों ने लगाई दूसरी फसल, गेंहू,सरसों के बाद गर्मी में लगाएगें तिलहन

बैकुण्ठपुर (आरएनएस)। राज्य शासन की प्राथमिकता के अनुसार वनाधिकार पत्रक धारियों को अच्छा सामाजिक जीवन देने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें उनकी वनाधिकार भूमि के उन्नयन के साथ उन्हे बेहतर आजीविका से जोडऩे के लिए व्यक्तिगत विकास कार्यों की स्वीकृति के साथ सामुदायिक विकास कार्यों की स्वीकृति भी प्रदान की जा रही है। उत्काषय के विचार व्यक्त करते हुए जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी कुणाल दुदावत ने बताया कि कलेक्टर कोरिया कुलदीप षर्मा के मार्गदर्षन में आने वाले समय में इन सभी वनाधिकार पत्रकधारी किसानों को एक निष्चित आय की सीमा मे लाने के लिए सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जा रहा है ताकि एक परंपरागत फसल के अलावा रबी और गर्मी की फसल के लिए भी किसान आगे आएं। कोरिया जिले में इस तरह के प्रयास अब कदम दर कदम आगे बढऩे लगे हैं। जिले के वनांचल जनपद सोनहत अंतर्गत ग्राम पंचायत पोड़ी में वनाधिकार पत्रकधारियों के ऐसे ही लगभग दो दर्जन से ज्यादा वनवासी परिवारों की तीस एकड़ से ज्यादा भूमि में अब दूसरी फसल गेंहू और सरसों लहलहाने लगी है। यहां के सभी आदिवासी किसान अब विभिन्न योजनाओं के सहयोग से उत्साहित होकर कहते हैं कि गेंहू के बाद हम अपने खेतों में गर्मी की उड़द और मक्के की खेती भी करेंगे।

जलसंचय, संरक्षण और संवर्धन के लिए केद्र स्तर पर पुरूस्कृत हो चुके सोनहत वनांचल के ग्राम पंचायत पोड़ी में दो दर्जन किसानों के वनाधिकार भूमि के उन्नयन के लिए महात्मा गांधी नरेगा और रूरबन मिषन योजना के अभिसरण से यहां 28 लाख रूपए की लागत से विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यो की स्वीकृति के बाद क्रियान्वयन के प्रथम चरण में ही चारों तरफ हरियाली है। यहां रहने वाले 22 किसानों के खेतों में परंपरागत धान की फसल के बाद गेंहू और सरसों की फसल लगी हुई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत यहां सामूहिक फलोद्यान की तैयारी के साथ भूमि सुधार, डबरी में मत्स्य पालन जैसे अनेक आजीविका के संसाधन अब इस पूरे 30 एकड़ के क्षेत्रफल में आजीविका में सुधार की नई पहल साबित होने लगे हैं। यहां पोड़ी ग्राम पंचायत के रहवासी वनाधिकार पत्रधारी आदिवासी किसान रघुनंदन की तीन एकड़, मनोज कुमार, दयाषंकर, टेकचंद, सरिता और अर्जुन की लगभग ढाई-ढाई एकड़, बंधुराम, सुरेष, विष्वनाथ और बाबूलाल की लगभग दो-दो एकड़, राजकुमारी, षिवनारायण, रामसागर, अर्जुन/हूबलाल, सुरेष धर्मपाल, रामप्यारे की लगभग एक-एक एकड़ वनाधिकार भूमि और रामसकल रामस्वरूप, और मुन्नीबाई की लगभग पचास-पचास डिसमिल भूमि को मिलाकर कुल 30 एकड़ भूमि को इस एफआरए क्लस्टर कार्य के अंतर्गत चयनित किया गया है। अभी इस क्षेत्र में घेराबंदी कार्य प्रगतिरत है। अपने खेतों के बीच खड़े इन किसानों के चेहरे पर मुस्कान और हाथ में मनरेगा का जाबकार्ड भी है।